



SATYADHEESH

सत्याधीश

यूपीएससी साप्ताहिक विस्तृत नोट्स

करेंट अफेयर्स • सप्ताह 34 • 17 अगस्त - 23 अगस्त 2026

50 नोट्स	37 खबरें जोड़ी गईं	GS2 • 30 पेपर मिश्रण	GS3 • 20
-------------	-----------------------	-------------------------	----------

विषय सूची

सभी नोट्स, पेपर के अनुसार

GS2	राज्यवस्था • शासन • सामाजिक न्याय • अंतर्राष्ट्रीय संबंध	30 नोट्स
राज्यवस्था एवं संविधान		12
शासन		3
सामाजिक न्याय		2
अंतर्राष्ट्रीय संबंध		13
GS3	अर्थव्यवस्था • विज्ञान-तकनीक • पर्यावरण • सुरक्षा	20 नोट्स
अर्थव्यवस्था		11
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		5
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी		4

हर नोट में

चर्चा में क्यों → याद रखने योग्य तथ्य → कीवर्ड के साथ मेन्स प्रश्न। एक ही खबर की रिपोर्टें जोड़ दी गई हैं।

समय कम है?

5 पेज के सार में सबसे ज़रूरी खबरें और अभ्यास प्रश्न हैं।

राज्यवस्था एवं संविधान

12

JUDICIARY & LANDMARK JUDGMENTS

P

M

17 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/106441

उच्चतम न्यायालय ने परमाणु दुर्घटना मुआवजे पर प्रस्तावित सीमा की संवैधानिकता और परमाणु ऊर्जा नियामक निकाय (AERB) में हितों के संभावित टकराव पर प्रश्न उठाए हैं

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय ने परमाणु दुर्घटना मुआवजे पर प्रस्तावित सीमा की संवैधानिकता और परमाणु ऊर्जा नियामक निकाय (AERB) में हितों के संभावित टकराव पर प्रश्न उठाए हैं।

संस्था	AERB: Atomic Energy Regulatory Body भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा और विकिरण संरक्षण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है।
तथ्य	SHANTI Act के तहत प्रस्तावित देयता सीमा (liability cap) ₹3,000 करोड़ है।
पद	परमाणु दुर्घटना मुआवजे से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने की।

मेन्स प्रश्न भारत में परमाणु सुरक्षा नियमों के संदर्भ में, औद्योगिक दायित्व सीमाओं (industrial liability caps) और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

CONSTITUTION, AMENDMENTS & BASIC STRUCTURE

P

M

2 रिपोर्टें जोड़ी गईं

17 अगस्त • NDTV • satyadheesh.in/news/106574

राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने केरल का नाम Keralam करने वाले बिल को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके द्वारा केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है।

संविधान	संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य के नाम, सीमाओं या क्षेत्रों को बदलने की शक्ति प्रदान करता है।
संविधान	संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं।
तथ्य	The Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026, नाम परिवर्तन के लिए विधायी वाहन था।

मेन्स प्रश्न भारत में राज्यों के नाम और सीमाओं के परिवर्तन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और इसके संघीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

ELECTIONS, ECI & ELECTORAL REFORMS

P

M

2 रिपोर्टें जोड़ी गईं

18 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/107051

सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन और मतदाताओं की पसंद की रक्षा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (

चर्चा में क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन और मतदाताओं की पसंद की रक्षा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को चुनावों पर काले धन के प्रभाव को समाप्त करने का निर्देश दिया।

संस्था	भारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए Election Commission of India (ECI) एक संवैधानिक निकाय है।
तथ्य	न्यायालय ने अवैध रूप से प्राप्त धन से संबंधित आपराधिक मामलों की जांच एक वर्ष के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया।
स्थान	कर्नाटक के बेल्लारी जिले में वह विशिष्ट काला धन जब्ती का मामला स्थित था जिसका उल्लेख याचिका में किया गया है।

मेन्स प्रश्न स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए काले धन के प्रभाव को कम करने में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

ELECTIONS, ECI & ELECTORAL REFORMS

P

3 रिपोर्टें जोड़ी गईं

18 अगस्त • NDTV • satyadheesh.in/news/107195

Gyanesh Kumar ने पटना में Electoral Literacy Clubs 2.0 लॉन्च किया

चर्चा में क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने युवाओं के बीच मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक विश्वास को बढ़ावा देने के लिए 'इलेक्टोरल लिटरसी क्लब्स 2.0' (Electoral Literacy Clubs 2.0) का शुभारंभ किया।

संस्था	मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC), भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के प्रमुख होते हैं।
तथ्य	Electoral Literacy Clubs 2.0 का लक्ष्य 15 लाख स्कूलों और 1,420 विश्वविद्यालयों तक पहुँचना है।
तथ्य	यह पहल चुनावी साक्षरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास निर्माण पर केंद्रित है।

मेन्स प्रश्न भारतीय चुनावी प्रक्रिया में सूचित भागीदारी सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में चुनावी साक्षरता के महत्व की चर्चा कीजिए।

सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों में फेस रिकग्निशन के इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस से पूछे सवाल

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) के उपयोग की आनुपातिकता और वैधता की समीक्षा की, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा और निजता के अधिकार के मध्य उत्पन्न तनाव को रेखांकित किया गया।

विज्ञान	FRS (Facial Recognition Systems) व्यक्तियों की पहचान करने के लिए वास्तविक समय (real-time) या छवियों से बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करते हैं।
तथ्य	दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान FRS का उपयोग करते हुए आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 व्यक्तियों की पहचान की।
पद	तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General of India) के रूप में कार्यरत हैं।

मेन्स प्रश्न निजता के अधिकार के संदर्भ में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) के उपयोग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने के लिए Article 142 का इस्तेमाल करने पर सहमति दी

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय ने NEET-UG के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के विरुद्ध दर्ज FIR को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया, जो असाधारण मामलों में न्याय सुनिश्चित करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति को रेखांकित करता है।

संविधान	अनुच्छेद 142: सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है।
संस्था	भारत का सर्वोच्च न्यायालय: देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।
तथ्य	Solicitor General द्वारा प्रदर्शनकारियों के बीच आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 व्यक्तियों की पहचान की गई।

मेन्स प्रश्न अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्तियों के दायरे और सीमाओं का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से विरोध के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के बीच संतुलन स्थापित करने के संदर्भ में। चर्चा कीजिए।

NMC ने डॉक्टरों के लिए सिंगल ID और हर 5 साल में रिन्यूअल का प्रस्ताव दिया

चर्चा में क्यों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने भारत भर में निर्बाध अभ्यास की सुविधा प्रदान करने हेतु चिकित्सकों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली बनाने के लिए एक मसौदा संशोधन प्रस्तावित किया है।

संस्था	NMC: National Medical Commission भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है।
तथ्य	लाइसेंस नवीनीकरण: सक्रिय स्थिति बनाए रखने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में अनिवार्य नवीनीकरण का प्रस्ताव।
संस्था	एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड: चिकित्सा पंजीकरण के संबंध में अपीलों की सुनवाई के लिए नामित निकाय।

मेन्स प्रश्न भारत में चिकित्सा चिकित्सकों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली स्वास्थ्य सेवा वितरण और व्यावसायिक जवाबदेही को किस प्रकार बेहतर बना सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

सुप्रीम कोर्ट: बंद कमरे में जातिसूचक टिप्पणी सार्वजनिक अपराध नहीं, चार्ज रद्द

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि बंद कमरे में जातिगत अपशब्दों का प्रयोग सार्वजनिक अपराध की श्रेणी में नहीं आता, और इस प्रकार SC/ST अधिनियम के दायरे को स्पष्ट किया।

अधिनियम	अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
संस्था	भारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India)।
तथ्य	न्यायालय ने SC/ST Act के तहत निजी विवादों और सार्वजनिक अपराधों के बीच अंतर स्पष्ट किया।

मेन्स प्रश्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संदर्भ में 'सार्वजनिक दृश्य' (public view) की न्यायिक व्याख्या और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की गरिमा की सुरक्षा पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

अमित शाह ने लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच की घोषणा की, सुरक्षा उपायों की स्थानीय मांग के बीच

चर्चा में क्यों न्यायिक सुगमता को बढ़ानेउन्नत न्यायिक सुगमता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना की घोषणा की है।

स्थान	लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है।
संस्था	लद्दाख में उच्च न्यायालय की पीठ, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का ही विस्तार होगी।
तथ्य	यह घोषणा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 20 अगस्त, 2026 को की गई थी।

मेन्स प्रश्न लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक पीठों की स्थापना न्याय की प्रभावी सुलभता सुनिश्चित करने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखने में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए।

सुप्रीम कोर्ट: सोशल मीडिया मॉब अटैक केस में गैंगस्टर एक्ट का गलत इस्तेमाल

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सोशल मीडिया पोस्ट से उत्पन्न हुई भीड़ द्वारा की गई हिंसा में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया गया।

संस्था	भारत का उच्चतम न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
तथ्य	उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट: संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक राज्य-विशिष्ट कानून।
तथ्य	निर्णय की तिथि: 21 जून, 2025।

मेन्स प्रश्न सांप्रदायिक अशांति को संबोधित करने के लिए कठोर संगठित अपराध विरोधी कानूनों के उपयोग के निहितार्थों और दंडात्मक कानूनों के दुरुपयोग को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को संवैधानिक निष्पादन विधि के रूप में बरकरार रखा

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इसकी वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए, फांसी की सजा को मृत्युदंड के एक संवैधानिक तरीके के रूप में बरकरार रखा।

अधि नियम	Code of Criminal Procedure (CrPC) की धारा 354(5) निष्पादन की विधियों से संबंधित है।
संस्था	भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक निकाय और संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णायक है।
तथ्य	न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस बात का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है कि घातक इंजेक्शन (lethal injection) फांसी की तुलना में अधिक मानवीय विकल्प है।

मेन्स प्रश्न भारत में मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता और इसके निष्पादन के तरीकों के नैतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

न्यायमूर्ति संजय करोल की सेवानिवृत्ति गृहणियों के आर्थिक योगदान की न्यायिक मान्यता और सामाजिक न्याय में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करती है

चर्चा में क्यों न्यायमूर्ति संजय करोल की सेवानिवृत्ति गृहणियों के आर्थिक योगदान की न्यायिक मान्यता और सामाजिक न्याय में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करती है।

पद	न्यायमूर्ति संजय करोल ने हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पटना उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
तथ्य	सुप्रीम कोर्ट ने जून 2026 के एक निर्णय में गृहणियों के मुआवजे को बढ़ाकर ₹63 लाख कर दिया।
संस्था	Amicus Curiae: न्यायालय द्वारा विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए नियुक्त एक तटस्थ तीसरा पक्ष।

मेन्स प्रश्न भारतीय न्यायिक ढांचे के भीतर गृहकार्य जैसे गैर-बाजार आर्थिक योगदानों को मान्यता देने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

सरकार की रिक्वेस्ट बढ़ने से 5 महीनों में 2.44 लाख सोशल पोस्ट हटाए गए

चर्चा में क्यों प्रेस सूचना ब्यूरो ने सूचित किया है कि संशोधित IT Intermediaries Rules के अंतर्गत, सरकारी विभागों ने पांच महीनों के भीतर 2.44 लाख सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का अनुरोध किया है।

अधिनियम	IT Intermediaries Rules: यह सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज द्वारा कंटेंट हटाने के संबंध में उनके दायित्वों को नियंत्रित करता है।
तथ्य	Takedown समय में कमी: संशोधित नियमों के तहत 36 घंटों से घटकर 3 घंटे।
तथ्य	अनुरोधों के स्रोत: सामग्री हटाने के 82% अनुरोध राज्य सरकारों से प्राप्त हुए।
संस्था	I4C: घोटाला और साइबर-संबंधित सामग्री की रिपोर्टिंग में शामिल सरकारी इकाई।

मेन्स प्रश्न सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती नियम (IT Intermediaries Rules) के अंतर्गत सामग्री हटाने के लिए सरकार की शक्तियों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों और इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

नए IRC के तहत भविष्य के लेबर विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया क्लीन स्लेट

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि 'उद्योग' की ऐतिहासिक परिभाषा स्वतः ही नए औद्योगिक संबंध संहिता (IRC) 2020 पर लागू नहीं होगी, जिससे श्रम विवादों के लिए एक नवीन कानूनी ढांचा सुनिश्चित होगा।

अधिनियम	Industrial Relations Code (IRC) 2020, Industrial Disputes Act, 1947 का स्थान लेता है।
संस्था	उच्चतम न्यायालय का निर्णय नए कोड के तहत श्रम कानूनों की व्याख्या के लिए 'क्लीन स्लेट' (clean slate) प्रदान करता है।
तथ्य	IRC 2020 को नवंबर 2025 तक लागू/प्रभावी करने का लक्ष्य रखा गया है।

मेन्स प्रश्न औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, नियोक्ताओं और श्रमिकों के लिए कानूनी निश्चितता के साथ औद्योगिक सद्भाव को संतुलित करने के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

Justice B.V. Nagarathna: 1978 का फैसला पलटने से कंपनियों को फायदा और वर्कर्स को नुकसान हो सकता है

चर्चा में क्यों न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना ने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत 'उद्योग' की परिभाषा के संबंध में नौ न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में असहमति व्यक्त की और श्रम अधिकारों के संभावित क्षरण के प्रति चेतावनी दी।

अधिनियम	Industrial Relations Code (IRC) 2020: Industrial Disputes Act 1947 जैसे पुराने कानूनों को प्रतिस्थापित करने वाला एक समेकित श्रम कानून।
संस्था	भारत का सर्वोच्च न्यायालय: नौ न्यायाधीशों की पीठ श्रम संरक्षण के लिए 'industry' के दायरे की व्याख्या कर रही है।
तथ्य	1978 बैंगलोर वाटर सप्लाई निर्णय: श्रमिक कल्याण की रक्षा के लिए 'उद्योग' की व्यापक परिभाषा स्थापित की।

मेन्स प्रश्न उदारीकरण के युग में 'उद्योग' की पुनर्व्याख्या ने निगमों और श्रमिकों के बीच सौदेबाजी की शक्ति (bargaining power) पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

NEET-UG लीक पर सुप्रीम कोर्ट की NTA से कड़ी पूछताछ, Nilekani टास्क फोर्स पर उठाए सवाल

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय ने NEET-UG प्रश्नपत्रों के लीक होने और विभिन्न कार्य बल (task forces) के बीच सुधारों के कार्यान्वयन में निरंतरता के अभाव के संबंध में National Testing Agency (NTA) से प्रश्न पूछे हैं।

संस्था	NTA: National Testing Agency एक स्वायत्त निकाय है जो NEET और JEE जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
पद	नंदन निलेकणी: UIDAI के पूर्व अध्यक्ष और परीक्षा सुधार के लिए टास्क फोर्स के वर्तमान प्रमुख।
तथ्य	SUPREME COURT ने NEET-UG परीक्षा के संबंध में 19 अगस्त, 2026 को अपनी टिप्पणियाँ दीं।

मेन्स प्रश्न भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और तकनीकी सुधारों को संस्थागत बनाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।

कम ही लोग जानते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी थी

चर्चा में क्यों पैलियेटिव केयर (palliative care) के लिए सार्वजनिक जागरूकता और बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण, पैसिव यूथेनेसिया (passive euthanasia) और 'लिविंग विल्स' (living wills) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के 2018 के निर्णय को चर्चा में लाया जा रहा है।

संस्था	AIIMS: नई दिल्ली में एक प्रमुख सार्वजनिक चिकित्सा अनुसंधान और तृतीयक देखभाल (tertiary care) अस्पताल।
तथ्य	पैसिव यूथेनेसिया (Passive Euthanasia): किसी मरीज को प्राकृतिक रूप से मृत्यु की ओर जाने देने के लिए जीवन-रक्षक उपचार (जैसे वेंटिलेटर) को वापस लेना।
तथ्य	लिविंग विल (Living Will): एक व्यक्ति द्वारा किया गया कानूनी घोषणापत्र जिसमें वह यह निर्दिष्ट करता है कि लाइलाज बीमारी की स्थिति में वह कौन से चिकित्सा उपचार चाहता है या नहीं चाहता है।

मेन्स प्रश्न भारत में 'लिविंग विल' (Living Will) और पैसिव इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) से जुड़े नैतिक और कानूनी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। राज्य उपशामक देखभाल (Palliative Care) के बुनियादी ढांचे में कैसे सुधार कर सकता है? विश्लेषण कीजिए।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

13

Saudi Arabia, Turkey और Pakistan ने किया डिफेंस समझौता, US ने दी तारीफ

चर्चा में क्यों सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देने के लिए 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौता' (Mecca Joint Defence Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा की गतिशीलता को प्रभावित करेगा।

तथ्य	Mecca Joint Defence Agreement पर 7 अगस्त को जेद्दाह में हस्ताक्षर किए गए।
विज्ञान	यह समझौता NATO के Article 5 पर आधारित है, जो सामूहिक रक्षा (collective defence) को अनिवार्य बनाता है।
स्थान	जेद्दाह वह स्थान है जहाँ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मेन्स प्रश्न मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता और दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना पर 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

BRICS समिट से पहले अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ से भारत-चीन संबंधों पर खतरा

चर्चा में क्यों अरुणाचल प्रदेश में कथित चीनी अतिक्रमण ने भारत और चीन के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे आगामी BRICS शिखर सम्मेलन प्रभावित होने की संभावना है।

स्थान	अरुणाचल प्रदेश: पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जो चीन, भूटान और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है।
संस्था	BRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना एक अंतर-सरकारी संगठन।
तथ्य	यह सीमा विवाद भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से संबंधित है।

मेन्स प्रश्न भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और ब्रिक्स (BRICS) ढांचे के भीतर बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की उसकी क्षमता पर सीमा विवादों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

दिल्ली मीटिंग में BRICS ने EU के कार्बन प्लान को "एकतरफा और भेदभावपूर्ण" बताया

चर्चा में क्यों नई दिल्ली में आयोजित 12वें पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में BRICS देशों ने सामूहिक रूप से EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) का विरोध किया और व्यापारिक निष्पक्षता एवं जलवायु वित्त पर अपनी चिंताओं को रेखांकित किया।

अंतः संगठन	BRICS: एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (तथा नए सदस्य) शामिल हैं।
विज्ञान	CBAM: EU में आयातित कार्बन-गहन उत्पादों पर एक कार्बन टैक्स।
तथ्य	यह बैठक BRICS का 12वां पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन थी।

मेन्स प्रश्न यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे एकपक्षीय व्यापार उपायों का ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों के जलवायु लक्ष्यों और आर्थिक हितों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।

Syria ने UN जांच के सामने दिखाया भारी मात्रा में न्यूक्लियर मटेरियल, IAEA ने की तारीफ

चर्चा में क्यों संयुक्त राष्ट्र की जांच के दौरान सीरिया ने IAEA को परमाणु सामग्री के कई टन का खुलासा किया, जो परमाणु अप्रसार में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की भूमिका को रेखांकित करता है।

संस्था	IAEA: International Atomic Energy Agency, संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ढांचे के भीतर एक स्वायत्त संगठन।
विज्ञान	परमाणु सुरक्षा (Nuclear Safeguards): वे उपाय जो यह सत्यापित करते हैं कि परमाणु सामग्री का उपयोग हथियारों के लिए नहीं किया जा रहा है।
तथ्य	सीरिया ने UN जांच को बशीर अल-असद युग से संबंधित सामग्री का खुलासा किया।

मेन्स प्रश्न वैश्विक परमाणु अप्रसार में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की भूमिका के महत्व और संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में परमाणु सामग्रियों की निगरानी से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

भारत ने आतंकवादियों की सूची में शामिल करने या उन्हें हटाने की प्रक्रिया में UN Security Co

चर्चा में क्यों भारत ने आतंकवादियों की सूची में शामिल करने या उन्हें हटाने की प्रक्रिया में UN Security Council की पारदर्शिता की कमी की आलोचना की है और इस निकाय को संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए उपयोग किए जाने से रोकने हेतु संरचनात्मक सुधारों का आह्वान किया है।

संस्था	UNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है।
तथ्य	1267 Al-Qaida Sanctions Committee: एक विशिष्ट UNSC निकाय जिसे Al-Qaida और उससे जुड़े व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध प्रतिबंध लागू करने का कार्य सौंपा गया है।
संस्था	स्थायी मिशन (Permanent Mission) UN: संयुक्त राष्ट्र में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनयिक मिशन।

मेन्स प्रश्न आतंकवाद विरोधी उपायों में निष्पक्षता बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और इसकी पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत और सिंगापुर के मंत्रियों ने मजबूत रिश्तों पर चर्चा की: ISMR में डिजिटल और आर्थिक विकास पर बातचीत

चर्चा में क्यों व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित चौथे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR) के दौरान भारतीय मंत्रियों ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से भेंट की।

स्थान	सिंगापुर: भारत की 'Act East' नीति के लिए एक प्रमुख ASEAN भागीदार।
तथ्य	अगस्त 2026 में चौथा भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR) आयोजित किया गया।
संस्था	व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership): भारत और सिंगापुर के बीच एक उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय ढांचा।

मेन्स प्रश्न भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों के संदर्भ में भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व की चर्चा कीजिए।

नई दिल्ली बैठक में रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने MAHASAGAR को जापान के FOIP के साथ जोड़ा

चर्चा में क्यों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के MAHASAGAR विजन को जापान की 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' (FOIP) पहल के साथ संरेखित करने हेतु जापानी समकक्षों के साथ बैठक की।

पद	राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं।
तथ्य	MAHASAGAR: हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत का समुद्री दृष्टिकोण।
तथ्य	FOIP: जापान की 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' (Free and Open Indo-Pacific) पहल।
स्थान	कुमामोटो: जापान का वह प्रान्त जो हाल ही में भूकंप से प्रभावित हुआ है।

मेन्स प्रश्न भारत-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित करने में भारत के 'महासागर' (MAHASAGAR) दृष्टिकोण को जापान की 'मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत' (FOIP) पहल के साथ संरेखित करने के महत्व की चर्चा कीजिए।

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने लद्दाख का दौरा किया और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री से भेंट की

चर्चा में क्यों अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने लद्दाख का दौरा किया और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री से भेंट की, जिसमें LAC पर जारी तनाव के बीच कश्मीर पर भारत की संप्रभुता के प्रति अमेरिका के रुख की पुनः पुष्टि की गई।

पद	सर्जियो गोर: भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए विशेष दूत।
तथ्य	गलवान संघर्ष (जून 2020): इसके परिणामस्वरूप 20 भारतीय सेना के जवानों की मृत्यु हुई।
स्थान	लद्दाख: 2019 में एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना।
तथ्य	अमेरिकी समर्थन: 2020 के संघर्षों के बाद भारत को रियल-टाइम इंटेलिजेंस और हाई-एल्टीट्यूड गियर प्रदान किया।

मेन्स प्रश्न हिमालयी क्षेत्र में सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

अमेरिका ने International Criminal Court पर लगाए नए sanctions

चर्चा में क्यों बेंजामिन नेतन्याहू के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के पश्चात, अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र (UN) और यूरोपीय संघ (EU) के साथ राजनयिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया है।

अंत. संगठन	ICC: एक अंतर-सरकारी संगठन और संधि-आधारित निकाय जो नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है।
तथ्य	ICC का मुख्यालय नीदरलैंड्स के द हेग (The Hague) में स्थित है।
अंत. संगठन	UN और EU ने ICC के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंधों की आधिकारिक रूप से निंदा की है।

मेन्स प्रश्न प्रमुख शक्तियों द्वारा लगाए गए एकपक्षीय प्रतिबंधों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC), की स्वतंत्रता और कार्यात्मकता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

Dr S Jaishankar 23 Aug को 27th IRIGC-TEC सेशन के लिए रूस जाएंगे

चर्चा में क्यों विदेश मंत्री एस. जयशंकर व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 27वें IRIGC-TEC सत्र की सह-अध्यक्षता करने हेतु रूस के दौरे पर हैं।

संस्था	IRIGC-TEC: भारत और रूस के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय निकाय।
पद	एस. जयशंकर: भारत के वर्तमान विदेश मंत्री।
पद	सर्गेई लावरोव: रूस के वर्तमान विदेश मंत्री।
तथ्य	अगस्त 2026 के लिए निर्धारित सत्र IRIGC-TEC का 27वां संस्करण है।

मेन्स प्रश्न बदलते वैश्विक परिवेश के बीच रूस के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में IRIGC-TEC के महत्व की चर्चा कीजिए।

यू.एस. का आरोप: भारत और 39 अन्य देशों ने चीन को टैरिफ से बचने में मदद की, \$28B का नुकसान

चर्चा में क्यों संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और अन्य 39 देशों पर चीन से होने वाले पारगमन (transshipment) को सुगम बनाने का आरोप लगाया है, जिसका उद्देश्य टैरिफ से बचना है। यह स्थिति संभावित रूप से व्यापारिक दंड और विनिर्माण लागत में वृद्धि का कारण बन सकती है।

- तथ्य** यू.एस. ने ट्रांसशिपमेंट घोटालों के कारण टैरिफ राजस्व में \$28 बिलियन के नुकसान का अनुमान लगाया है।
- स्थान** भारत, मैक्सिको और वियतनाम को ट्रांसशिपमेंट घोटाले के प्राथमिक सूत्रधारों के रूप में पहचाना गया।
- तथ्य** 'The Great Transshipment Scam' रिपोर्ट 24 जुलाई, 2026 को जारी की गई थी।

मेन्स प्रश्न वैश्विक व्यापार की गतिशीलता और वैश्विक विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति पर पारगमन (transshipment) प्रथाओं के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, सीमा विवाद के समाधान और भारत-चीन संबंधों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के 25वें दौर के लिए बीजिंग के दौरे पर हैं

चर्चा में क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, सीमा विवाद के समाधान और भारत-चीन संबंधों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के 25वें दौर के लिए बीजिंग के दौरे पर हैं।

- पद** अजीत डोवाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के रूप में कार्यरत हैं।
- स्थान** गलवान घाटी लद्दाख क्षेत्र में एक उच्च-ऊँचाई वाला दर्रा है, जो 2020 के संघर्ष का स्थल था।
- तथ्य** यह भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधियों (Special Representatives) के बीच वार्ता का 25वां दौर है।

मेन्स प्रश्न भारत-चीन सीमा विवाद के प्रबंधन में विशेष प्रतिनिधियों (Special Representatives) के तंत्र के महत्व और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

ट्रेड बढ़ाने के लिए जापान में 200 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगे भारत के गोयल

चर्चा में क्यों वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने और उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा करने के लिए जापान जा रहे 200 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

- तथ्य** जापान का लक्ष्य एक दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करना है।
- स्थान** Nagoya और Osaka जापान के प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र हैं।
- विज्ञान** सेमीकंडक्टर और AI भारत-जापान व्यापार चर्चाओं के प्रमुख केंद्र बिंदु हैं।
- संस्था** Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) प्राथमिक व्यापार ढांचा है जिसकी समीक्षा की जा रही है।

मेन्स प्रश्न वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और तकनीकी प्रगति के संदर्भ में भारत-जापान आर्थिक सहयोग के महत्व की चर्चा कीजिए।

अर्थव्यवस्था

11

EXTERNAL SECTOR, TRADE & FDI

P

18 अगस्त • NDTV • satyadheesh.in/news/107451

जुलाई में भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड \$44.24 बिलियन पहुंचा, इलेक्ट्रॉनिक्स में 57.4% का उछाल

चर्चा में क्यों माल दुलाई की बढ़ती लागत के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में भारी उछाल के कारण जुलाई में भारत का वस्तु निर्यात रिकॉर्ड 44.24 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

- तथ्य** | जुलाई में भारत का वस्तु निर्यात रिकॉर्ड \$44.24 बिलियन तक पहुंच गया।
- तथ्य** | जुलाई में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 57.4% बढ़कर लगभग \$5.9 बिलियन हो गया।
- तथ्य** | चीन को निर्यात में वार्षिक आधार पर 64.57% की वृद्धि के साथ \$2.2 बिलियन दर्ज किया गया।
- तथ्य** | इंजीनियरिंग सामान का निर्यात 17.7% बढ़कर \$12.24 बिलियन हो गया।
- तथ्य** | मध्य पूर्व को निर्यात 8.6% बढ़कर \$5.7 बिलियन हो गया।

मेन्स प्रश्न भारत के व्यापारिक निर्यात (merchandise exports) की वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों और समुद्री व्यापार पर वैश्विक भू राजनीतिक व्यवधानों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

INFRASTRUCTURE (ENERGY, PORTS, ROADS, RAILWAYS)

P

2 रिपोर्टें जोड़ी गईं

18 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/107828

PNG अपनाते की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार दे रही है 200 standard cubic metres सस्ती गैस

चर्चा में क्यों भारत सरकार ने घरेलू पाइपड नेचुरल गैस (PNG) के उपयोग को गति देने के उद्देश्य से सिटी-गैस वितरकों को 200 मानक घन मीटर सस्ती APM गैस की सब्सिडी की घोषणा की है।

- तथ्य** | प्रोत्साहन: प्रत्येक नए घरेलू-PNG कनेक्शन पर 200 मानक घन मीटर सस्ती गैस।
- तथ्य** | पेबैक अवधि में कमी: 10 वर्ष से घटकर लगभग 3 वर्ष।
- तथ्य** | तंत्र: प्राकृतिक गैस के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र (APM)।
- तथ्य** | कार्यान्वयन: 1 सितंबर, 2026 से शुरू होने वाले छह महीनों की अवधि में दो किशतों में प्रोत्साहन (Incentives) प्रदान किए जाएंगे।

मेन्स प्रश्न भारत में पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (PNG) की ओर संक्रमण को गति देने में प्रशासित मूल्य तंत्र (APM) और सरकारी सब्सिडी के महत्व की चर्चा कीजिए।

MONETARY POLICY, RBI & BANKING

P

M

19 अगस्त • NDTV • satyadheesh.in/news/108111

RBI ने फास्ट फ्लोटिंग-रेट लोन का प्रस्ताव दिया, हर 3 महीने में बदलेंगे इंटररेस्ट रेट

चर्चा में क्यों RBI ने ब्याज दर संचरण (interest rate transmission) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से फ्लोटिंग-रेट होम लोन के रिसेट चक्र को वार्षिक से घटाकर प्रति तीन माह करने का एक मसौदा प्रस्तावित किया है।

- संस्था** | RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
- तथ्य** | प्रस्तावित पुनः निर्धारण आवृत्ति: प्रत्येक तीन महीने (पूर्व में वार्षिक)।
- तथ्य** | अनुप्रयोज्यता: विशेष रूप से गृह ऋण (home loans) को लक्षित करता है; व्यक्तिगत और ऑटो ऋण (personal and auto loans) को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
- तथ्य** | प्रवासन की समय सीमा: मौजूदा उधारकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 1 अप्रैल, 2029 तक माइग्रेट करना होगा।

मेन्स प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गृह ऋणों के लिए ब्याज दर पुनः निर्धारण चक्र (interest rate reset cycle) को छोटा करने के प्रस्ताव का भारत में अधिक कुशल मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) में योगदान कैसे होता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

SEBI Chairman ने SMEs के लिए IPO नियमों में बदलाव की घोषणा की, महंगी अंडरराइटिंग सिस्टम्स पर निशाना

चर्चा में क्यों SEBI अध्यक्ष ने अक्षम और महंगी अंडरराइटिंग प्रणालियों के समाधान तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं में सुधार हेतु SME IPO नियमों की समीक्षा की घोषणा की है।

संस्था	SEBI: Securities and Exchange Board of India भारत में प्रतिभूति बाजार (securities market) का प्राथमिक नियामक है।
तथ्य	SME Platform: लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने हेतु एक समर्पित मंच।
विज्ञान	पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS): किसी व्यक्ति के निवेश पोर्टफोलियो का एक पेशेवर प्रबंधन।

मेन्स प्रश्न एसएमई (SMEs) के लिए आईपीओ (IPO) नियमों को सुव्यवस्थित करना किस प्रकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा दे सकता है और भारतीय पूंजी बाजारों को और अधिक गहरा बना सकता है, चर्चा कीजिए।

महंगाई की चिंता के बीच RBI ने पॉलिसी रेट 5.25% पर बरकरार रखा

चर्चा में क्यों RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ने निरंतर बनी हुई मुद्रास्फीति की चुनौतियों और अनुमानित मुख्य मुद्रास्फीति (headline inflation) के उच्चतम स्तर को देखते हुए नीतिगत दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा।

तथ्य	RBI पॉलिसी रेट: अगस्त की बैठक तक 5.25%।
तथ्य	अनुमानित हेडलाइन मुद्रास्फीति का शिखर: Q3 2026-27 में 5.9%।
तथ्य	FY27 के लिए अनुमानित मुख्य मुद्रास्फीति (core inflation): 4.3%।
पद	संजय मल्होत्रा: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर।

मेन्स प्रश्न एक अस्थिर व्यापक आर्थिक परिवेश में मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

SEBI विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए लिक्विड स्टॉक्स पर collateral में 15%-20% की कमी की योजना बना रहा है

चर्चा में क्यों विदेशी निवेशकों द्वारा की गई व्यापक बिकवाली के पश्चात, SEBI विदेशी संस्थागत पूंजी को आकर्षित करने के उद्देश्य से तरल शेयरों (liquid stocks) के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं (collateral requirements) को 15%-20% तक कम करने की योजना बना रहा है।

संस्था	SEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
तथ्य	रिपोर्टिंग अवधि तक भारतीय इक्विटी में विदेशी स्वामित्व 17 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया।
तथ्य	अक्टूबर 2024 और जून 2026 के बीच विदेशियों द्वारा \$50 बिलियन से अधिक मूल्य के भारतीय इक्विटीज (equities) बेचे गए।

मेन्स प्रश्न विदेशी संस्थागत निवेश (FII) को आकर्षित करने में पूंजी बाजार सुधारों के महत्व और भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

SEBI ने BSE Sensex क्लोजिंग ऑक्शन में हेरफेर करने के लिए JPMorgan की एक इकाई और एक स्थानीय फर्म पर प्रतिबंध लगाया है

चर्चा में क्यों SEBI ने BSE Sensex क्लोजिंग ऑक्शन में हेरफेर करने के लिए JPMorgan की एक इकाई और एक स्थानीय फर्म पर प्रतिबंध लगाया है, जो नव-परिचलित ऑक्शन-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।

संस्था	SEBI: Securities and Exchange Board of India, भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
तथ्य	भारतीय शेयर बाजार का मूल्यांकन लगभग \$5.1 ट्रिलियन है।
स्थान	BSE Sensex: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स।
विज्ञान	नीलामी-आधारित प्रणाली (Auction-based system): शेयरों की समापन कीमत निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक तंत्र, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप है।

मेन्स प्रश्न उच्च आवृत्ति व्यापार (High-frequency trading) और परिष्कृत बाजार हेरफेर की तकनीकों के दौर में बाजार की अखंडता बनाए रखने में नियामकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

6 August को लोकसभा ने Section 10A में संशोधन करने वाला बिल पास किया

चर्चा में क्यों लोकसभा ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पारित किया है, ताकि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को UPI लेनदेन के लिए शुल्क लेने की अनुमति प्रदान की जा सके।

अधि नियम	Payment and Settlement Systems Act, 2007: भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करता है।
संस्था	NPCI: भारत में रिटेल भुगतान और सेटलमेंट सिस्टम संचालित करने वाला अंब्रेला संगठन।
तथ्य	UPI की वार्षिक लागत: वर्तमान में ₹20,000 करोड़ तक अनुमानित है।
विज्ञान	UPI: NPCI द्वारा विकसित एक रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम।

मेन्स प्रश्न यूपीआई (UPI) पर लेनदेन शुल्क लागू करने के वित्तीय समावेशन और भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे की स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

कीमतें कम करने के लिए भारत ने 10 लाख टन ड्यूटी-फ्री कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी

चर्चा में क्यों भारत सरकार ने खुदरा कीमतों में हो रही वृद्धि को स्थिर करने और आपूर्ति-पक्ष के झटकों (supply-side shocks) के प्रबंधन हेतु 10 लाख टन कच्चे चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति प्रदान की है।

तथ्य	आयात कोटा: 10 लाख टन कच्ची चीनी।
तथ्य	रिटेल चीनी की कीमतों में साल-दर-साल लगभग 13% की वृद्धि हुई।
तथ्य	स्टॉकहोल्डिंग सीमा: थोक उपभोक्ताओं के लिए 15 दिनों की खपत तक सीमित।
संस्था	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) चीनी और खाद्य प्रसंस्करण नियमों की देखरेख करता है।

मेन्स प्रश्न भारतीय कृषि बाजार में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने में आयात-निर्यात नीतियों और स्टॉकहोल्डिंग विनियमों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

Apple Rs 62,500-crore की स्कीम के तहत भारत में MacBook और iPad मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकता है

चर्चा में क्यों केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Apple जैसी वैश्विक कंपनियों को भारत में उच्च-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' (MPMS) की घोषणा की।

योजना	Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) का बजट Rs 62,500 करोड़ है।
तथ्य	यह योजना 14 महीनों के भीतर तीन भारतीय स्मार्टफोन ब्रांडों के विकास को लक्षित करती है।
पद	अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के केंद्रीय मंत्री हैं।

मेन्स प्रश्न मोबाइल फोन निर्माण योजना किस प्रकार भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित कर सकती है और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता को कैसे बढ़ा सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी के असर से भारत का म(Wait, let me re-evaluate the translation for "backfires" in this context - usually means "उल्टा पड़ना" or "विफल होना")

[illegible]

तथ्य	मक्का भारत के कुल इथेनॉल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है।
तथ्य	मक्का आधारित एथेनॉल के लिए सरकारी खरीद मूल्य ₹71.86 प्रति लीटर है।
तथ्य	भारत दशकों में पहली बार ममभारत दशकों में पहली बार मम

मेन्स प्रश्न भारत की एथेनॉल सम्मिश्रण नीति के घरेलू खाद्य सुरक्षा और व्यापार संतुलन पर पड़ने वाले आर्थिक एवं कृषि संबंधी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

Defence Dept ने जारी की लिस्ट: स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए ₹3,070 करोड़ की 405 आइटम

चर्चा में क्यों रक्षा उत्पादन विभाग ने ₹3,070 करोड़ मूल्य की 405 रक्षा वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए छठी 'पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट' जारी की है।

तथ्य	छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (Positive Indigenisation List) में 405 वस्तुएं शामिल हैं।
तथ्य	सूचीबद्ध मदों की व्यावसायिक क्षमता का अनुमान ₹3,070 करोड़ है।
संस्था	SRIJAN Defence Portal वह मंच है जिसका उपयोग स्वदेशीकरण की समयसीमा (indigenisation timelines) को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
पद	इस पहल के लिए रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) नोडल निकाय है।

मेन्स प्रश्न रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में 'पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट' (सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची) के योगदान और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

पूर्वी भारत में मिला पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवन, जो 3.497 बिलियन साल पुराना है

चर्चा में क्यों पूर्वी भारत के सिंहभूम ब्लॉक में 3.497 अरब वर्ष पुराने सूक्ष्म जीवाश्मों (microfossils) की खोज प्रारंभिक सूक्ष्मजीवी जीवन और जटिल चयापचय मार्गों (metabolic pathways) के प्रमाण प्रदान करती है।

स्थान	सिंहभूम भूवैज्ञानिक ब्लॉक पूर्वी भारत में स्थित है।
विज्ञान	3.497 अरब वर्ष पुराने सूक्ष्म जीवाश्म (Microfossils) प्रारंभिक जीवन रूपों की उपस्थिति का संकेत देते हैं।
विज्ञान	ज्वालामुखी की राख में जैविक अवशेषों के विश्लेषण के लिए Spectroscopic विधियों का उपयोग किया गया।

मेन्स प्रश्न जीवन के विकास और पृथ्वी के प्रारंभिक चयापचय मार्गों (metabolic pathways) को समझने में भूवैज्ञानिक और जैविक खोजों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

Fram2 मिशन के दौरान अंतरिक्ष में लिए गए पहले X-rays

चर्चा में क्यों Fram2 मिशन ने अंतरिक्ष में पहली बार नैदानिक एक्स-रे (diagnostic X-rays) का सफलतापूर्वक संचालन किया, जो दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों के लिए उन्नत चिकित्सा इमेजिंग की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है।

विज्ञान	Fram2: मार्च 2025 में कक्षा में चिकित्सा प्रौद्योगिकियों (medical technologies) का परीक्षण करने के लिए प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष मिशन।
विज्ञान	Dragon spacecraft: वह वाहन जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक चालक दल और कर्गों को पहुँचाने के लिए किया जाता है।
तथ्य	इस मिशन ने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (microgravity) वातावरण में नैदानिक रूप से पर्याप्त X-ray चित्र सफलतापूर्वक उत्पन्न किए।

मेन्स प्रश्न दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए स्वायत्त चिकित्सा निदान प्रौद्योगिकियों के विकास के महत्व और सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण (microgravity) द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

तरपुर में दुनिया के सबसे पुराने कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर ₹3.31 प्रति यूनिट पर चालू

चर्चा में क्यों भारत का प्रथम बड़े पैमाने का वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा केंद्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, अपने जीवन विस्तार (life extension) की प्रक्रिया के दौरान विश्व के सबसे पुराने वाणिज्यिक रिएक्टर के रूप में निरंतर संचालित हो रहा है।

विज्ञान	तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र (TAPS) भारत का पहला बड़े पैमाने का वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा केंद्र है।
तथ्य	तरापुर वर्तमान में ₹3.31 प्रति यूनिट की टैरिफ दर पर बिजली का उत्पादन करता है।
विज्ञान	TAPS का निर्माण 1964 में General Electric और Bechtel के उपकरणों के साथ किया गया था।
विज्ञान	Three Mile Island (1979), Chernobyl (1986), और Fukushima (2011) सहित प्रमुख वैश्विक परमाणु दुर्घटनाओं ने सुरक्षा उन्नयन (safety upgrades) को प्रभावित किया।

मेन्स प्रश्न निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर भारत के संक्रमण में परमाणु ऊर्जा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, तथा साथ ही पुराने बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

ISRO Chairman ने 4 महीने में अन-क्यूएड Gaganyaan लॉन्च करने की घोषणा की

चर्चा में क्यों ISRO के अध्यक्ष ने आगामी मानव रहित गगनयान मिशन की घोषणा की है, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विज्ञान	Gaganyaan: अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजने के उद्देश्य से भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन।
विज्ञान	PSLV: Polar Satellite Launch Vehicle, ISRO के उपग्रह मिशनों के लिए एक प्रमुख रॉकेट।
तथ्य	ISRO का लक्ष्य: एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और चंद्र एवं शुक्र मिशन संचालित करना।

मेन्स प्रश्न भारत को एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने में गगनयान मिशन के महत्व और अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

4

सुप्रीम कोर्ट: फसल नुकसान के बावजूद हाथी गलियारों की रक्षा करें, कोई रुकावट न हो

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हाथी गलियारों में आने वाली बाधाओं का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है, जिसमें फसल के नुकसान की तुलना में वन्यजीवों के आवागमन को प्राथमिकता दी गई है।

संस्था	MoEFCC: Ministry of Environment, Forest and Climate Change वन्यजीव संरक्षण के लिए नोडल निकाय है।
पर्यावरण	हाथी गलियारे (Elephant corridors): खंडित आवासों के बीच आवाजाही के लिए हाथियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्दिष्ट मार्ग।
तथ्य	न्यायालय ने हाथियों के विरुद्ध हथियारों या दंडात्मक कार्रवाई के उपयोग को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया।

मेन्स प्रश्न भारत के खंडित पारिस्थितिक तंत्रों में प्रवासी गलियारों के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

केरल की एयर क्वालिटी दक्षिण भारत में सबसे खराब, स्टडी में 25 शहर PM10 स्टैंडर्ड में फेल

चर्चा में क्यों CSTEP के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि दक्षिण भारत में वायु प्रदूषण में केरल का स्थानीय योगदान सर्वाधिक है, जहाँ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत 25 शहर PM10 मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं।

तथ्य	दक्षिण भारत में वायु प्रदूषण में केरल का स्थानीय योगदान 65% है।
तथ्य	NCAP के तहत दक्षिण भारत के 25 शहरों को गैर-प्राप्ति (non-attainment) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
संस्था	CSTEP (Council on Sustainable Ecological Systems and Technologies) ने इस अध्ययन को संचालित किया।
योजना	NCAP (National Clean Air Programme) उन शहरों को लक्षित करता है जहाँ PM10 और PM2.5 की सांद्रता निर्धारित सीमाओं से अधिक है।

मेन्स प्रश्न भारत में 'एयरशेड' (वायुमंडल क्षेत्र) स्तर पर वायु गुणवत्ता के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण नियंत्रण हेतु अंतर-राज्यीय सहयोग को बेहतर बनाने के उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए।

Justice एस.वी.एन. की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बैंच

चर्चा में क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) के संबंध में एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराते हुए जिला कलेक्टरों को स्कूली पाठ्यक्रम में SWM शिक्षा को एकीकृत करने का आदेश दिया गया है।

संस्था	भारत का उच्चतम न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
तथ्य	जिला कलेक्टर: अपशिष्ट प्रबंधन निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार जिलों के प्रशासनिक प्रमुख।
स्थान	भारत: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर न्यायालय के निर्देश का भौगोलिक दायरा।

मेन्स प्रश्न भारत में शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों के समाधान में सामुदायिक भागीदारी और शैक्षिक सुधारों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

अगस्त्यमाला लैंडस्केप के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया बेदखली फ्रेमवर्क का आदेश

चर्चा में क्यों राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण, उच्चतम न्यायालय ने अगस्त्यमलाई क्षेत्र से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बलों का उपयोग करते हुए एक व्यवस्थित निष्कासन रूपरेखा (eviction framework) को अनिवार्य किया है।

स्थान	अगस्त्यमलाई परिदृश्य (landscape) तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
पर्यावरण	कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व और कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य, अगस्त्यमलाई क्षेत्र के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं।
तथ्य	उच्चतम न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों के निष्कासन के लिए अर्धसैनिक बलों के उपयोग का सुझाव दिया।

मेन्स प्रश्न पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-sensitive zones) को अतिक्रमण से बचाने में आने वाली चुनौतियों और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह टेलीग्राम पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + वीडियो · हर रविवार साप्ताहिक · हिंदी और अंग्रेज़ी · मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh · satyadheesh.in/upsc/reports

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।